निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) शहरों को संवारने के विशिष्ट उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र में कोई योजना आरम्भ नहीं की गई थी। तथापि, गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना अप्रैल, 1972 में इस उद्देश्य से आरम्भ की गई थी कि ऐसी गन्दी बस्तियों में अनिवार्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जायें जिन्हें कम से कम 10 वर्ष तक हटाना अपेक्षित नहीं है। यह योजना 31 मार्च, 1974 तक केन्द्रीय क्षेत्र में थी और इसे पांचवीं योजना के प्रारम्भ में राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इन्दौर शहर आता है।

विवरण

गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत आए शहर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता की राशि का विवरण।

क्रम सं०	शहर का नाम	1972–73 तथा 1973–74 में दी गई अनुदान की राशि
1.	कलकत्ता	5,89,00,000
2.	बम्बई	2,55,83,500
3.	दिल्ली	1,75,77,500
4.	मद्रास	2,95,16,000
5.	हैदराबाद	30,35,800
6.	अहमदाबाद	14,00,850
7.	बंगलौर	72,82,350
8.	कानपुर	1,32,19,000
9.	लखनऊ	1,24,04,999
10.	पूना	27,31,000
11.	नागपुर	1,02,18,198
12.	इन्दौर	28,06,000
13.	जयपुर	46,57,440
14.	श्रीनगर	30,00,000
15.	पटना	21,18,000
16.	कोचीन	9,70,000
17.	लुधियाना	39,66,660
18.	कटक	7,88,000
19.	गोहाटी	1,81,000
20.	रोहतक	7,89,500

चावल के क्षेत्र बनाना

969. श्री मीठा लाल पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल के कितने क्षेत्र हैं और क्या चावल की खपत वाले क्षत्रों को चावल क्षेत्रों में नहीं रखा गया है ; और उदाहरणतया राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र के स्थान पर दक्षिण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों के बनाने के समय उन सिद्धान्तों को ध्यान में नहीं रखा गया जिनकी ध्यान में रखना जरूरी है और सरकार की इस बारे में इस समय क्या नीति है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क). देश में इस समय लगभग 15 चावल जोन हैं । उत्तरी और दक्षिणी चावल जोन, जहां प्रत्येक जोन में कुछ राज्य शामिल हैं, को छोड़कर अन्य जोन लगभग एक राज्यीय जोन है । दक्षिणी चावल जोन में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु और पांडिचेरी के चावल उपभोक्ता क्षेत्र शामिल हैं । राजस्थान के उपभोक्ताओं की चावल की बढ़िया किस्म की मांग को पूरा करने में सहायता करने के लिये राजस्थान को उत्तरी चावल जोन में शामिल कर लिया गया है ।

(ख) स्थिति, जोकि समय-समय पर बदलती रहती है, की जरूरत के मुताबिक चावल जोन बनाये जाते हैं, उनका विस्तार किया जाता है । 1976–77 विपणन मौसम के दौरान, क्षेत्र के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी चावल जोन बनाया गया है ।

चीनी पर से नियंत्रण हटाना

970. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी पर से नियंत्रण हटाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) और (ख) : सरकार चीनी नीति पर जब अगली बार विचार करेगी तब अन्य प्रश्नों के साथ-साथ चीनी से नियंत्रण उठाने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

Reimbursement to the allottees of Rajouri Garden Flats

971. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the price of the DDA (LIG) Flats at Rajouri Garden (G-8) was higher than the price of DDA (LIG) Flats at Prasad Nagar and Kalkaji;

(b) if so, the reasons for this anomaly; and

(c) whether Government are considering for suitable reimbursement to the allottees of Rajouri Garden flats?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) : (a) Yes, Sir.

(b) The difference in price of flats arises due to difference in design, plinth area and the rate at which the work is awarded.

(c) No, Sir.

Memoranda from Individuals/Institutions of Maharashtra regarding Education Policy

972. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) how many representations and memoranda have been received by the Government since 25th March, 1977 from individuals and institutions of the State of Maharashtra in regard to educational policy of Government; and

(b) what action Government have taken or propose to take in respect of the said representations and memoranda?